चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 संख्या 243 श्री विजय पुरम, शुक्रवार , 11 सितम्बर 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संस्थान निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (प.सू.का.)

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के संस्थान निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के निदेशक और एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक सहित कई केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली दोनों में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन की संपूर्ण कार्यप्रणाली को बदलकर 'ज़ीरो कैजुआलिटी' का लक्ष्य निर्धारित किया और देश को इस स्थिति तक पहुँचाया। हमने कई आपदाओं का 'ज़ीरो कैजुआलिटी' के साथ सफलतापूर्वक सामना भी किया है जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री शाह ने कहा कि पहले आपदा को केवल राहत एवं पुनर्वास की दृष्टि से देखा जाता था। आज हम जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा 'ज़ीरो कैजुआलिटी'–इन तीनों स्तंभों के साथ एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसी दिशा में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमारी कार्य–संस्कृति का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। आपदा आने पर सरकार के सभी विभाग सक्रिय रूप से कार्य करते हैं ,अब हमें नए अनुसंधान के बल पर इस प्रक्रिया को और तीव्रता से आगे बढ़ाना चाहिए और सतत निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। जिस प्रकार आपदा से निपटने में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई है, उसी प्रकार आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में भी हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय अंततः पर्यावरण संरक्षण

शेष पृष्ठ 4 पर

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वच्छता ही सेवा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की

अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (प.सू.का.)

आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज राज्यो के शहरी विकास मंत्रियों, प्रधान सचिवों, शहरी विकास विभाग के अधिकारियों और राज्य मिशन निदेशकों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वच्छता ही सेवा–2026 की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2026 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस वर्ष अभियान का विषय 'स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत' रखा गया है। यह विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा ज़िम्मेदारी की भूमिका को रेखांकित करता है।

स्वच्छता ही सेवा 2026 के प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों और अधिक भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला–युवा फॉर स्वच्छता, सफाईमित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जनभागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल हैं। स्वच्छता से समृद्धि के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था और कचरे से संपदा जैसी पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभियान के प्रमुख क्षेत्रों और देशभर में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। अभियान के दौरान व्यापक नागरिक भागीदारी, स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन और स्वच्छता के स्पष्ट परिणाम सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। राज्य विभागों से अपने–अपने कार्यालय परिसरों, पर्यटन स्थलों और जल निकायों में स्वच्छता अभियान चलाने में अग्रणी भूमिका निभाने को कहा गया।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोगों से 17 सितंबर को अपने घर से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से स्वयं अपने घर की सफाई करने और शाम को घर में दीप जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह दीप स्वच्छ घर, स्वस्थ परिवार और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होगा और हासिल की गई स्वच्छता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान को 'सेवा संकल्प' की भावना से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि स्वच्छता केवल एक महीने की गतिविधि न रहकर निरंतर जन–भागीदारी का संकल्प बने।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का उल्लेख करते

शेष पृष्ठ 4 पर

टैगोर सभागार में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह–2026 का शुभारंभ

बेहतर पोषण परिणाम प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर ज़ोर

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) शहरी परियोजना द्वारा आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई) सभागार में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह–2026 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में समाज कल्याण सह वित्त सचिव श्री हेमंत कुमार, समाज कल्याण निदेशक श्री मोहित मिश्रा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक श्री एच. एम. सिद्धाराजू सहित स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विभागों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

9वां राष्ट्रीय पोषण माह–2026 का आयोजन 9 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2026 तक किया जा रहा है। भारत सरकार की प्रमुख पोषण पहल पोषण अभियान के अंतर्गत आयोजित इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के बीच पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के महत्व को और सुदृढ़ करना है।

सभा को संबोधित करते हुए समाज कल्याण सचिव ने बेहतर पोषण परिणाम प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया।

राष्ट्रीय पोषण माह के प्रमुख विषय

- आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन
- ताज़ा एवं गर्म पकाए गए भोजन
- सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही

- बाल विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)–मातृ स्वास्थ्य के लिए नकद सहायता

समाज कल्याण निदेशक ने भी महत्वपूर्ण विचार एवं उत्साहवर्धक संदेश साझा करते हुए सामूहिक ज़िम्मेदारी, सामुदायिक भागीदारी तथा विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला, ताकि पोषण अभियान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उद्घाटन कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रशासन, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, विभिन्न विभागों, सामुदायिक संगठनों और नागरिकों ने पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने तथा प्रत्येक बच्चे और परिवार के लिए स्वस्थ, सुपोषित और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई।

विश्व पर्यटन दिवस–2026 पर पर्यटन विभाग आयोजित करेगा प्रचार वीडियो/रील प्रतियोगिता

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय द्वारा पर्यटन से जुड़े हितधारकों के सहयोग से 27 सितंबर, 2026 को द्वीपों में विश्व पर्यटन दिवस–2026 मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय "पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता" है।

समारोह का उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाने को बढ़ावा देना, युवाओं तथा पर्यटन से जुड़े हितधारकों के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की विविध पर्यटन संभावनाओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना है।

विश्व पर्यटन दिवस–2026 के समारोह के एक भाग के रूप में पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रभावशाली व्यक्तित्वों, डिजिटल सामग्री निर्माताओं तथा अन्य इच्छुक प्रतिभागियों के लिए प्रचार वीडियो/रील प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य नवाचारी डिजिटल सामग्री के माध्यम से द्वीपों के पर्यटन आकर्षणों, अनुभवों, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। प्रतिभागी 1 से 3 मिनट की अवधि के लघु पर्यटन प्रचार वीडियो/रील तैयार कर सकते हैं, जिसमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाए।

इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्र तट, साहसिक एवं जल आधारित गतिविधियां, पारिस्थितिकी पर्यटन, वन्यजीव, संस्कृति, विरासत, परंपराएं, स्थानीय व्यंजन, कला, हस्तशिल्प तथा अन्य विशिष्ट पर्यटन अनुभव शामिल किए जा सकते हैं। उक्त प्रतियोगिता के विजेताओं को क्रमशः 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 5,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि तथा प्रमाण–पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रविष्टियों का मूल्यांकन रचनात्मकता, मौलिकता, सामग्री की गुणवत्ता, पर्यटन आकर्षण, डिजिटल माध्यम के प्रभावी उपयोग तथा समग्र प्रचारात्मक मूल्य के आधार पर किया जाएगा। निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यूनतम 10 पात्र प्रविष्टियां/प्रतिभागिताएं प्राप्त होना आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी को किसी भी प्रविष्टि को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में सभी इच्छुक सामग्री निर्माता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, डिजिटल कहानीकार तथा अन्य इच्छुक प्रतिभागियों को प्रस्तावित प्रतियोगिता में भाग लेने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को डिजिटल रूप से सक्षम, नवाचारी तथा पर्यटकों के अनुकूल पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रविष्टियां ई–मेल **photounitiptdepartment@gmail.com** के माध्यम से 23 सितंबर, 2026 को शाम 4 बजे तक भेजी जा सकती हैं।

विश्व पर्यटन दिवस–2026 : पर्यटकों एवं आम जनता के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा

विजय पुरम, 10 सितंबर।

विश्व पर्यटन दिवस, 2026 के अवसर पर, जो 27 सितंबर, 2026 को "पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता" विषय के साथ मनाया जाएगा, सद्भावना के रूप में पर्यटकों और आम जनता के लिए चाथम आरा मिल, समुद्रिका संग्रहालय, मानवविज्ञान संग्रहालय, मत्स्य संग्रहालय तथा सेल्यूलर जेल संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

मॉडल स्कूल में पुलिस ने चलाया नशा जागरूकता कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने 10 सितंबर, 2026 को लगभग 2,000 विद्यार्थियों की संख्या वाले राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अबर्डीन बाज़ार में नशा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

शेष पृष्ठ 4 पर

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी रेडी कार्यक्रम पर दो दिवसीय कार्यशाला हुई

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकॉयस) के समन्वय से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी रेडी कार्यक्रम पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन निदेशालय स्थित आपदा प्रबंधन भवन के प्रशिक्षण कक्ष, श्री विजय पुरम में किया गया।

कार्यक्रम के प्रथम दिन सभी ज़िला प्रशासनों, संबंधित विभागों तथा ज़िला एवं ग्राम स्तर की सुनामी रेडी समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य सुनामी से निपटने की तैयारियों को सुदृढ़ करना, संस्थागत समन्वय को बढ़ाना तथा संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में सामुदायिक क्षमता एवं लचीलापन विकसित करना था।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आपदा प्रबंधन सचिव श्रीमती पल्लवी सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने सुनामी रेडी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ज़मीनी स्तर पर तैयारियों को मजबूत करने के लिए ज़िला प्रशासन, संबंधित विभागों और सामुदायिक स्तर की समितियों द्वारा समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

इससे पूर्व, उद्घाटन सत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आपदा प्रबंधन निदेशक श्रीमती प्रियंका कुमारी ने प्रारंभिक संबोधन दिया और सुनामी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने तथा सभी हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला। हैदराबाद स्थित इनकॉयस के निदेशक डॉ. टी. एम. बालकृष्णन नायर ने ऑनलाइन माध्यम से स्वागत भाषण दिया और सुनामी संबंधी खतरों के प्रति सामुदायिक तैयारी एवं लचीलेपन को बढ़ाने में सुनामी रेडी कार्यक्रम के महत्व पर ज़ोर दिया।

उद्घाटन सत्र का समापन आपदा प्रबंधन निदेशालय के सहायक निदेशक (प्रशासन) श्री जनिक राम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इसके पश्चात आयोजित तकनीकी सत्रों में सुनामी के खतरे तथा भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का अवलोकन कराया गया। इसके बाद यूनेस्को–आईओसी सुनामी रेडी कार्यक्रम, इसके संकेतकों एवं क्रियान्वयन रूपरेखा तथा सुनामी रेडी संकेतकों के आकलन पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए।

प्रतिभागियों को सुनामी रेडी के लिए तैयारी एवं प्रतिक्रिया के साथ–साथ सुनामी रेडी मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और प्रमाणों के बारे में भी जागरूक किया गया। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी रेडी कार्यक्रम की स्थिति : प्रगति, कमियां एवं आगे की कार्ययोजना विषय पर

शेष पृष्ठ 4 पर

दक्षिण अण्डमान में अंतर–विद्यालय शतरंज, योग एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं 15 सितंबर से

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा कार्यालय द्वारा 15 से 22 सितंबर, 2026 तक राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में बालक एवं बालिकाओं के लिए अंतर–विद्यालय शतरंज, योग एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं की समय–सारणी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	कक्षा	दिनांक
1.	शतरंज	पहली से पांचवी	16/09/2026 (बालक एवं बालिकाएं)
		छठवीं से आठवीं	
		नौवीं से बारहवीं	17/09/2026 (बालक
2.	योग	छठवीं से आठवीं	18/09/2026 (बालक
		नौवीं से दसवीं	19/09/2026 (बालक
3.	टेबल टेनिस	जन्मतिथि 2010 एवं उससे कम (अंडर–16)	21/09/2026 (बालिकाएं)
			22/09/2026 (बालक)

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ——————————पृष्ठ 1 का शेष

ही है। पर्यावरण संरक्षण, जोखिम न्यूनीकरण, रेजिलियंस (लचीलापन) और व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकृइनके कारण भारत धीरे–धीरे विश्व में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है। मिशन लाइफ, प्रो–प्लैनेट पीपल और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल आपदा रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 'शून्य हताहत' दृष्टिकोण को केवल आपदा स्थल पर ही लागू नहीं करना है। आपदा घटित होने से रोककर भी 'ज़ीरो कैजुआलिटी' प्राप्त की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी राष्ट्रध्यक्षों से हटकर ऐसे सुरक्षित एवं संतुलित विश्व की कल्पना की है। श्री अमित शाह ने कहा कि एक समय था जब एनआईडीएम का पूर्ववर्ती रूप (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र) कृषि भवन के एक कोने में लगभग निष्क्रिय पड़ा हुआ था लेकिन वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे नया जीवन प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। विषय की व्यापकता एवं विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान को गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस संस्थान में प्राण फूँकने का महत्वपूर्ण कार्य किया। छप्पड का वर्तमान स्वरूप बदली हुई एवं सुदृढ़ भूमिका के साथ देश के समक्ष आया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में एनआईडीएम और एनडीएमए दोनों की सार्थकता एवं प्रासंगिकता और अधिक बढ़ने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही, विज्ञान के नए–नए अनुप्रयोगों और विस्तारित क्षेत्रों के कारण नई प्रकार की आपदाओं का उदय भी संभव है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, नीति निर्धारण से लेकर प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन तक की ज़िम्मेदारी इन दोनों संस्थानों के बीच साझा रूप से विभाजित है। कुछ क्षेत्रों में दोनों संस्थान मिलकर कार्य भी कर रहे हैं।

श्री अमित शाह ने निर्देश दिए कि सभी हितधारक अपने–अपने विभागों में एजेंडे के क्रियान्वयन के लिए एक सेल गठित करें और विभागीय प्रमुख कम–से–कम तीन माह में एक बार इसकी समीक्षा बैठक अवश्य आयोजित कर इस विषय को प्राथमिकता दें।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि एनआईडीएम और एनडीएमए को दुनिया भर में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों का अध्ययन कर उनके निष्कर्षों को भारत में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू करने का प्रयास करना चाहिए। कृषि विभाग को पाकिस्तान की तरफ से आने वाले टिड्डे दलों के हमलों से बचाव की स्थायी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए विदेशों में अपनाए जा रहे बेहतरीन उपायों को देश में लागू किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में गंभीरता होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो इस विषय के प्रति सही मायने में गंभीर हों।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनआईडीएम एवं एनडीएमए मिलकर देश भर के लिए दिशानिर्देश जारी करें। इनमें प्रत्येक आपदा के संबंध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए–इसकी स्पष्ट रूपरेखा हो। एनआईडीएम प्रशिक्षण का कार्य करे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) एवं अन्य संबंधित एजेंसियाँ मिलकर इन दिशानिर्देशों को धरातल पर उतारें।

श्री अमित शाह ने कहा कि अनुसंधान के माध्यम से आपदा के कारणों को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर प्रभावी बचाव संभव हो सकता है। प्रत्येक आपदा के बाद एनडीएमए एवं एनआईडीएम की एक संयुक्त टीम गठित की जाए, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को भी सम्मिलित किया जाए। ये चारों संस्थाएँ मिलकर क्षति के कारणों का अध्ययन करें, एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।

श्री अमित शाह ने कहा कि एनआईडीएम अनुसंधान, नवाचार, नीति समर्थन, प्रशिक्षण और विभागीय सहयोग का एक राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। हमें इन चारों स्तंभों को और अधिक सशक्त बनाते हुए नए क्षितिजों का विकास करना है। अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण, नीति समर्थन एवं विभागीय सहयोग–इन चारों क्षेत्रों में अभी भी अछूते क्षितिज हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में हमें स्पर्श करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनआईडीएम ने इस दिशा में प्रयास भी किए हैं। ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को विभागीय साइलोस से बाहर निकालने की आवश्यकता है। हमें आने वाले दिनों में विभागीय मर्यादाओं से ऊपर उठकर समन्वित रूप से कार्य करने की आदत विकसित करनी होगी।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ——————————पृष्ठ 1 का शेष

हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि अभियान 17 सितंबर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री की सेवा भावना और संकल्प को स्वच्छता के उद्देश्य से जोड़ना है।

माननीय प्रधानमंत्री के 'मन की बात' में दिए संदेश का उल्लेख करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि जब किसी स्थान को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोग स्वयं लेते हैं, तो बदलाव केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस स्थान की पहचान को भी बदल देता है। उन्होंने कहा कि इसलिए स्वच्छता को लोगों का सामूहिक संकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर समाज के सभी वर्गों में स्वच्छता अभियान चलाए जाने चाहिए। इनमें समावेशिता और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने ने राज्यों से 1 अक्टूबर तक व्यापक योजना और जागरूकता गतिविधियां चलाने को कहा, ताकि देशभर में 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' श्रमदान आयोजित किया जा सके। राज्य के शिक्षा और खेल विभागों से युवाओं और खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ने को कहा गया है। उन्होंने सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों, महापौरों, उप महापौरों, वार्ड पार्षदों, नगर आयुक्तों और राज्यों की प्रमुख हस्तियों से अपने–अपने क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों में इस राष्ट्रव्यापी श्रमदान का नेतृत्व करने तथा व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने नगर निकायों से आवासीय सोसाइटियों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों–आरडब्ल्यूए को भी अभियान से जोड़ने को कहा। इसके लिए वार्डों और आरडब्ल्यूए के बीच स्वच्छता प्रतियोगिताएं आयोजित करने और प्रमुख आरडब्ल्यूए स्थानों पर स्वच्छता से जुड़े संदेशों का प्रचार करने का सुझाव दिया गया।

2 अक्टूबर स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष परिषद बैठकें और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश को जन–जन तक पहुंचाया जाएगा और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया जाएगा।

बैठक में सफाई कर्मियों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सफाईमित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविरों के महत्व पर भी बल दिया गया। इन शिविरों के माध्यम से पात्र सफाई कर्मियों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने, स्वास्थ्य जांच कराने और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। अधिक प्रभाव के लिए ऐसे शिविर पूरे वर्ष नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करने का भी आग्रह किया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत जनभागीदारी, खेल आयोजनों, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक गीतों तथा स्वच्छता गीतों के माध्यम से प्रभावी और नए तरीकों से जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। अभियान के दौरान की गई गतिविधियों की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और स्वच्छता अभियान के ज़मीन पर मापने योग्य परिणाम तथा प्रत्येक नागरिक के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई। हालांकि अभियान आधिकारिक रूप से 17 अक्टूबर को समाप्त होगा, राज्यों से पूरे वर्ष स्वच्छता की इस गति को बनाए रखने का आग्रह किया गया है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी रेडी ——————————पृष्ठ 1 का शेष

भी एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम के प्रथम दिन का समापन संवादात्मक चर्चा, शंकाओं के समाधान तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के साथ हुआ।

मॉडल स्कूल में पुलिस ने चलाया नशा ——————————पृष्ठ 1 का शेष

कार्यक्रम के दौरान थाना अबर्डीन के प्रभारी निरीक्षक एवं थाना प्रभारी श्री विजय कुमार ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार जायसवाल, मुख्य आरक्षक मोहम्मद रफीक़, ममता पॉल और आरक्षक रोज़ा के साथ सुबहकालीन प्रार्थना के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। संवादात्मक सत्र में नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के साथ–साथ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत इसके कानूनी परिणामों पर चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नशे की लत के दीर्घकालिक दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया तथा उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यार्थियों ने सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया और पुलिस दल द्वारा उनकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान किया गया।

दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाने के साथ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने नशे से दूर रहने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। इस पहल का सभी ने स्वागत किया और इसने युवाओं में जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी तथा नशा मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य के प्रति दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने आम जनता से इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग करने तथा नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी विश्वसनीय जानकारी को साझा करने की अपील की है। ऐसी जानकारी दूरभाष नंबरों 112 (आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली), 03192–232100 (पुलिस नियंत्रण कक्ष), 03192–236641 (पुलिस अधीक्षक (ज़िला), दक्षिण अण्डमान कार्यालय), 1933 (मानस) तथा 9531856080 (पुलिस नशा–रोधी शाखा) के माध्यम से पुलिस को दी जा सकती है। सूचना देने वालों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा तथा उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

ट्राइबएक्स स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुरू

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए ट्राइबएक्स स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। ट्राइबएक्स मंत्रालय का डिजिटल शिक्षण मंच है, जो भारत के जनजातीय ज्ञान, संस्कृति, भाषाओं, कला, वस्त्र, संग्रहालय विज्ञान और सतत आजीविका पद्धतियों पर संरचित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों की पांच धाराओं में प्रवेश के लिए पंजीकरण खुले हैं। इनमें जनजातीय भाषा : संताली (ओलचिकी), संग्रहालय विज्ञान एवं जनजातीय संग्रहालय प्रबंधन, जनजातीय संस्कृति एवं कला, सतत जनजातीय संस्कृति–आधारित आजीविका पद्धतियां तथा जनजातीय वस्त्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सभी शिक्षार्थियों के लिए 50 से अधिक निःशुल्क प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों के लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों में जनजातीय ज्ञान विशेषज्ञों और कारीगरों से सीखने की सुविधा लचीले मिश्रित माध्यम में प्रदान की जाती है। इनमें एक माह की इंटर्नशिप भी शामिल है और ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ढांचे के अंतर्गत वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। प्रत्येक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम का पाठ्यक्रम शुल्क 7,500 रुपये है।

इन डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

जनजातीय कल्याण विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पंजीकरण अब खुले हैं। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधिकारिक ट्राइबएक्स पोर्टल **https://tribal.gov.in/TribeX.aspx** पर जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पात्र विद्यार्थी 9933210933 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी पात्र विद्यार्थियों, विशेष रूप से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से ट्राइबएक्स में नामांकन कराने, जनजातीय ज्ञान प्रणालियों से सीखने और ट्राइबएक्स के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है।

जेएनआरएम में मना विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) द्वारा आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जीबी पंत अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एवं समन्वय जेएनआरएम के सहायक प्रोफेसर श्री सुदेश कुमार द्वारा जेएनआरएम की मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के तत्वावधान में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ जेएनआरएम के सहायक प्रोफेसर डॉ. बिनितेंद्र नाथ मोंगल के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास ने मुख्य वक्तव्य दिया तथा विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए सुरक्षित एवं सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर ज़ोर दिया।

संवादात्मक सत्र में जीबी पंत अस्पताल से टेली–मानस की परामर्शदाता श्रीमती गीता रानी साहा तथा टेली–मानस की परियोजना समन्वयक श्रीमती अंबिका पॉल ने भाग लिया। उन्होंने आत्महत्या रोकथाम, तनाव एवं कठिन परिस्थितियों से निपटने की रणनीतियों, समय पर हस्तक्षेप तथा सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सहायता के महत्व पर चर्चा की।यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्यक्रम का समापन सामूहिक शपथ के साथ हुआ, जिसमें जेएनआरएम समुदाय ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा आत्महत्या रोकथाम संबंधी पहलों को समर्थन देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

जंगलीघाट और कैम्पबेल बे के पशुपालकों को दिया गया प्रशिक्षण

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा आज पशुपालकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत जंगलीघाट और कैंपबेल बे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम पशु चिकित्सालय, जंगलीघाट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें आवास व्यवस्था, आहार, स्वास्थ्य देखभाल, प्रजनन प्रबंधन और रोगों की रोकथाम शामिल थी। सत्र के दौरान बकरी पालकों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न सहायता योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

इसी दिन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत किसान खेत पाठशाला के तहत सुअर पालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पशु चिकित्सालय, कैंपबेल बे द्वारा राजीव नगर निकोबारी सामुदायिक भवन तथा पिलो भाबी सुनामी आश्रय स्थल स्थित किसान के खेत में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बेहतर उत्पादकता और आय सृजन के लिए वैज्ञानिक तरीके से सुअर पालन, उचित आहार, आवास व्यवस्था तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ये कार्यक्रम द्वीपों में पशुपालकों की क्षमता निर्माण तथा वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग किसानों के कल्याण के लिए इस प्रकार के क्षेत्र–स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोड़ियाघाट में मसाला फसलों की खेती पर प्रशिक्षण प्रारम्भ

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

यूटी–एटीएमए के अंतर्गत के प्रोथरापुर खंड में 'मसाला फसलों की खेती, कटाई उपरांत प्रबंधन, कटाई, प्रसंस्करण एवं भंडारण की कार्य–पद्धतियां' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दक्षिण अण्डमान के ग्राम पंचायत बिड़नाबाद के कोडियाघाट गांव में श्री टी. मोहम्मद के खेत में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किसानों के तकनीकी ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि मसाला फसलों की वैज्ञानिक खेती, कटाई, कटाई उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा मसाला उत्पादों के उचित भंडारण के संबंध में उनकी दक्षता में वृद्धि हो सके। बेहतर उत्पादकता, गुणवत्ता तथा उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उन्नत कार्य–पद्धतियों को अपनाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में ग्राम पंचायत बिड़नाबाद के सरपंच श्री वी. कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सत्र में दक्षिण अण्डमान के सहायक निदेशक (कृषि), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), सीपीघाट के विषय विशेषज्ञ, दक्षिण अण्डमान के कृषि अधिकारी तथा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता और प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसान भी उपस्थित रहे।

उद्घाटन सत्र के दौरान किसानों को मसाला फसलों की वैज्ञानिक खेती के महत्व तथा उचित खेत प्रबंधन एवं कटाई उपरांत प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कुल 23 किसान भाग ले रहे हैं।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय की यूजी एवं पीजी सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर–दिसंबर में

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति/चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (एनईपी/सीबीसीएस) पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर/दिसंबर, 2026 में जेएनआरएम केंद्र में आयोजित की जाएंगी। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इन परीक्षाओं के लिए पंजीकरण कराने के इच्छुक पात्र पूर्व विद्यार्थियों को 15 सितंबर, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक जेएनआरएम के परीक्षा अनुभाग से संपर्क करने की सूचना दी गई है।

एमवी चुगलम 16 सितंबर को कैंपबेल बे के लिए रवाना होगा

श्री विजय पुरम, 10 सितंबर।

मालवाहक जहाज़ एमवी चुगलम 16 सितंबर, 2026 को शाम 4 बजे हैडो घाट से कार निकोबार, चावरा, तरेसा, कच्छाल एवं ननकौड़ी होते हुए कैंपबेल बे के लिए रवाना होगा। जहाज़ संबंधित बंदरगाहों पर माल उतारने/लोड करने का कार्य पूरा होने के तुरंत बाद श्री विजय पुरम के लिए रवाना होगा।

उक्त यात्रा के लिए माल की बुकिंग 11 सितंबर, 2026 से वाणिज्यिक शाखा में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक शुरू होगी। माल की लोडिंग 13 सितंबर, 2026 से शुरू होगी।

प्राप्त विज्ञप्ति में सभी माल प्रेषकों को आगे सलाह दी गई है कि वे परिवहन किए जाने वाले माल की वास्तविक मात्रा के अनुसार ही माल की बुकिंग करें, क्योंकि अतिरिक्त माल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, प्रधानाचार्य का कार्यालय, नर्सिंग स्कूल
जी. बी. पंत अस्पताल परिसर, श्री विजय पुरम

वॉक–इन–इंटरव्यू

F.No. 1-34/SON/DHS/2013/ दिनांक : 09 सितंबर 2026

नर्सिंग स्कूल में अंग्रेजी एवं कंप्यूटर विषयों के लिए क्रमशः 30 घंटे एवं 35 घंटे की अवधि हेतु अल्पकालिक अनुबंध शिक्षकों के चयन के लिए वॉक–इन–इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित दिनांक 24/09/2026 को अपराह्न 4.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करें।

क्र.सं.	पद का नाम	वॉक–इन–इंटरव्यू की तिथि एवं समय
1	**पीजीटी शिक्षक (अंग्रेजी एवं कंप्यूटर विज्ञान)**	तिथि एवं समय : 29.09.2026 को प्रातः 10.00 बजे से स्थान : नर्सिंग स्कूल, पुराना ओपीडी भवन, जी.बी. पन्त अस्पताल, श्री विजय पुरम

अनुबंध शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	शिक्षण	रिक्तियां	आयु सीमा	समेकित एवं निश्चित कुल मेहनताना	आवश्यक योग्यता
1	**अंग्रेजी**	**01**		पारिश्रमिक 1000 रुपये प्रति घंटा तय किया जाएगा, अधिकतम छूट रु. 25,000.00 प्रति माह	आवश्यक : 1) संबंधित भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री 2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री 3) अंग्रेजी और हिंदी मीडिया में शिक्षण में दक्षता
2	**कंप्यूटर**	**01**			(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. या बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी) या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय के लिए समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा। या (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. या बी.टेक (किसी भी स्ट्रीम) और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एससी (कंप्यूटर साइंस)/एमसीए या समकक्ष या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (कंप्यूटर साइंस/बीसीए या समकक्ष और विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या (v) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (vi) अंग्रेजी और हिंदी मीडिया में शिक्षण में दक्षता

नियम एवं शर्तें :

1. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां नर्सिंग स्कूल, पुराना ओपीडी भवन, जी.बी. पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम में 24.09.2026 अपराह्न 4.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। आवेदन जमा करते समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
2. अल्पकालिक अनुबंध शिक्षकों को निर्धारित घंटों के अनुसार सिद्धांत एवं प्रायोगिक कक्षाएं लेना, 100 अंकों की परीक्षा आयोजित करना तथा अंक सूची (मार्क लिस्ट) प्रधानाचार्य, नर्सिंग स्कूल को प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. नियुक्ति पूर्णतः अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर होगी।
4. अभ्यर्थी की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
5. अल्पकालिक अनुबंध शिक्षक किसी भी प्रकार की सुविधा जैसे अवकाश, चिकित्सीय सुविधा, पास/पीटीओ, परिवहन आदि के पात्र नहीं होंगे।
6. चयन शैक्षणिक अंकों, अनुभव एवं साक्षात्कार अंकों के आधार पर कुल 100 अंकों में किया जाएगा।
7. सभी अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति/संलग्नता आदेशों से समर्थित होने चाहिए।
8. यह नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग/नर्सिंग स्कूल में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
9. कार्य से अनुपस्थिति की स्थिति में मानदेय से आनुपातिक कटौती की जाएगी।
10. साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।
11. पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के क्रम संख्या 10 के कॉलम 7 में दिए गए अंक योजना के अनुसार स्वयं अंक अंकित करने होंगे।

$$\text{मार्क वेटेज फॉर्मूला} = \frac{\text{बोर्ड/यूनिवर्सिटी में प्राप्त अंक}}{\text{अधिकतम अंक}} \times \text{अनुमत मैक्स. अंक}$$

निम्नलिखित योजना के अनुसार (केवल 2 दशमलव अंक तक) अंकों को पूर्णांकित करने की अनुमतिन हीं है।

श्रेणी मैक्स. शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के लिए योजना के अनुसार स्वीकार्य अंक

श्रेणी	मैक्स. शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के लिए योजना के अनुसार स्वीकार्य अंक					
	सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष (12वीं)	ग्रेजुएशन	पोस्ट–ग्रेजुएशन	बी.एड	अतिरिक्त योग्यता	अनुभव
पीजीटी	5	15	35	10	2 अंक एमएड के लिए 1 अंक एम.पी.एच. के लिए 1 अंक. अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 अंक पीएचडी के लिए 5	10

12. अनुभव अंक पूर्णकालिक शिक्षण हेतु 0.2 अंक प्रति माह एवं अंशकालिक शिक्षण हेतु 0.1 अंक प्रति माह की दर से दिए जाएंगे। प्रति वर्ष 02 अंक, अधिकतम 10 अंक, मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेज में शिक्षण अनुभव के आधार पर।
13. साक्षात्कार 15 अंकों का होगा।
14. मेरिट सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा केवल चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रधानाचार्य, नर्सिंग स्कूल

संविदा के आधार पर स्नातकोत्तर शिक्षक के पद के लिए आवेदन प्रारूप

पासपोर्ट आकार का फोटो लगाए

शिक्षण जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है (कृपया विकल्प पर (√) का निशान लगाएं) (i) अंग्रेजी (ii) कंप्यूटर		**अंग्रेजी**		**कंप्यूटर**
1)	नाम			
2)	लिंग (पुरुष/महिला)			
3)	पिता/पति का नाम			
4)	जन्म तिथि			
5)	दिनांक (24.09.2026) को आयु	वर्ष	महीने	दिन
6)	शैक्षणिक योग्यता			
7)	स्थायी पता			
8)	संचार के लिए स्थायी पता (विस्तृत पता)			
9)	संपर्क संख्या (मोबाइल, दूरभाष)			

10) योग्यता और अन्य योग्यताओं के लिए वेटेज

क्र. सं.	शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्त अंक विश्वविद्यालय/बोर्ड	अधिकतम प्राप्त अंक	योजना के अनुसार अधिकतम अंक	स्व–अंकन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2	सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष (12 वीं)				5		
3	मान्यताप्राप्त संस्थान से स्नातक				15		
4	पीजी (संबंधित विषयों के साथ)				40		
5	बी.एड.				10		
6	2 अंक एमएड के लिए 1 अंक एम.पी.एच. के लिए 1 अंक. अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 अंक पीएचडी के लिए				5		
7	मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रासंगिक क्षेत्र में शिक्षण का अनुभव				10		
	कुल				**85**		

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूं कि उपरोक्त पद के लिए मेरा नाम शामिल करने से पहले या बाद में कोई भी जानकारी झूठी या गलत होने या अपात्रता पाए जाने पर उसे रद्द किया जा सकता है।

स्थान :
तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनः प्रगति, सहयोग और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (हि.स.)। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12–13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। यह ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का भारत का चौथा अवसर होगा। इसका थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण है।

ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह प्रमुख मंच है, जहां ये प्रमुख देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को तैयार करते हैं। निरंतर संवाद के जरिए यह बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। ये समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही यह सदस्य देशों को अपने अनुभव को साझा करने और साझा चुनौतियों का समाधान भी तलाशने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है।

यह आयोजन ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। भारत 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसके तहत वह चौथी बार इस समूह की अध्यक्षता संभाल रहा है। भारत की अध्यक्षता का मार्गदर्शक विषय है, "सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण"। ये विषय भारत के मौजूदा उपलब्धियों को मजबूत करने और संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। इसके साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान–केंद्रित और परिणामोन्मुख मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है।

दुनिया की चार उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संक्षिप्त नाम ब्रिक्स एक बहुत बड़े समूह का रूप ले चुका है। ये चार महाद्वीपों तक फैला एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल ब्लॉक है।

इसकी यात्रा चार देशों के बीच संवाद से शुरू होकर आज के कहीं अधिक व्यापक समूह तक पहुची है। इसकी सदस्यता के लगातार विस्तार के साथ इसमें तेल–समृद्ध देश, अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं और दक्षिण–पूर्व एशिया के साझेदार भी शामिल होते गए। इस विस्तारित व्यवस्था के केंद्र में आज भारत है, जो इस समूह की स्थापना के बाद से चौथी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है।

ब्रिक्स में 11 प्रमुख देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ये सदस्य देश सामूहिक रूप से विश्व की 49.5 फीसदी आबादी, वैश्विक जीडीपी के 40 प्रतिशत और विश्व व्यापार के 26 फीसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आँकड़े उनकी उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय और आर्थिक क्षमता को रेखांकित करते हैं।

ब्रिक्स के विस्तारित सदस्य–समूह ने एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका तक इसकी भौगोलिक पहुँच को भी व्यापक बनाया है। यह विविधता बड़े बाजारों, प्राकृतिक संसाधनों, तकनीकी क्षमताओं और विकास के विभिन्न अनुभवों को एक साझा मंच पर लेकर आती है।

'ब्रिक' का संक्षिप्त नाम वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक्स पेपर में गढ़ा गया था। इकोनॉमेट्रिक एनालिसिस के आधार पर इस शोध–पत्र में अनुमान लगाया गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन अगले पांच दशकों के दौरान विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। इन देशों की बढ़ती आर्थिक शक्ति और तीन महाद्वीपों में फैली उनकी विशाल भौगोलिक पहुंच ने उनके उभरते वैश्विक महत्व को रेखांकित किया।

केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई–कॉमर्स नियमों में संशोधन किया

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई–कॉमर्स) नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, सर्च रिजल्ट में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई–कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी।

पिछली कीमत से आशय छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों में उत्पाद की सबसे कम कीमत से है। कंपनियां ऐसे तरीके से सर्च रिजल्ट में बदलाव नहीं कर सकेंगी। नए नियमों से ई–कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता–केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष एक जनवरी से लागू होंगे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियम डिजिटल मार्केटप्लेस से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कम कर व्यापार सुगमता को मजबूत करेंगे। प्रत्येक ई–कॉमर्स कंपनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की शिकायत निवारण व्यवस्था से जुड़ना होगा। शिकायतकर्ता को कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति भी देनी होगी। इसके अलावा आयातित वस्तुओं के मामले में आयातक का विवरण और मूल देश की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

जूनियर महिला एशिया कपः भारत ने पाकिस्तान को 19–0 से रौंदा, रिकॉर्ड जीत के साथ सेमीफाइनल में किया प्रवेश

मोकी, (चीन) 10 सितंबर (हि.स.)। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने शानदार आक्रामक प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को महिला जूनियर एशिया कप–2026 के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19–0 से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ने मुकाबले के चारों क्वार्टर में गोल दागे और एकतरफा जीत दर्ज की।

भारत ने पहले क्वार्टर में पांच, दूसरे में पांच, तीसरे में तीन और अंतिम क्वार्टर में छह गोल किए। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा आंकड़े भी भारत के एकतरफा दबदबे की गवाही देते हैं। भारत ने कुल 19 गोल किए, जबकि उसे 18 पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला। पाकिस्तान पूरे मुकाबले में न तो कोई गोल कर सका और न ही पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक हासिल कर सका।

इस शानदार जीत के साथ भारत ने महिला जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का सामना क्वार्टर फाइनल–4 में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा।

इतिहास के पन्नों में 11 सितम्बर : 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन और स्वामी विवेकानंद का ओजस्वी भाषण

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (हि.स.)। आज से 132 वर्ष पूर्व आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के महान दार्शनिक और संत स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद ने संबोधन की शुरुआत "अमेरिका की बहनों और भाइयों" कहकर की, जिसे सुनकर सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। यह संबोधन केवल श्रोताओं के हृदय को ही नहीं छू गया, बल्कि भारतीय अध्यात्म और सनातन संस्कृति के आदर्शों को भी विश्व पटल पर उजागर कर गया।

विवेकानंद ने अपने वक्तव्य में सभी धर्मों की एकता, सहिष्णुता और मानवता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही विभिन्न आस्थाओं और संस्कृतियों को अपनाकर उन्हें समान सम्मान देता आया है। उनके शब्दों ने न केवल भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि धर्म विभाजन का नहीं, बल्कि मानवता को जोड़ने का माध्यम है। यह भाषण आज भी विश्व इतिहास की अमूल्य धरोहर माना जाता है, जिसने भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई ऊंचाई प्रदान की।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र– 1906 – महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ़्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन आरंभ किया।
1919 – अमेरिकी नौसेना ने होंडुरास पर आक्रमण किया।
1922 – आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सचित्र दैनिक समाचार पत्र द सन न्यूज पेक्टोरियल की शुरूआत।
1939–इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1941–अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का निर्माण शुरू हुआ।
1951 – इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी फ्लोरेंस चैडविक। उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे।
1961 – विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना।
1965 – भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुर्की शहर पर कब्ज़ा किया।
1968 – एयर फ्रांस का विमान संख्या 1611 नाइस के निकट दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 89 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों की मौत।
1996 – राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित।
2001 – अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व पेंटागन पर आतंकवादी हमले में 6 हज़ार से अधिक लोग मरे।
2003 – चीन के विरोध के बावजूद तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा से अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश मिले।
2005 – गाजा पट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य शासन समाप्त करने की घोषणा।
2006 – पेस और डेम की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीता।
2006 – प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारतीय नागरिकता की मांग की।
2006 – अमेरिकी अंतरिक्ष यान अटलांटिस अंतरिक्ष के साथ जुड़ा।
2007 – येरूशलम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा।

भारत मंडपम में 27–28 अक्टूबर तक होगा इस्टिक 2026 का आयोजन

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (हि.स.)। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में आयोजित होने वाला इस्टिक 2026 (इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन – कोलोबोरेशन समिट) का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर तक भारत मंडपम में किया जाएगा। तीन दिवसीय इस आयोजन में देश–विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप, नीति–निर्माता, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े विशेषज्ञ एक मंच पर जुटेंगे।

सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, डीप–टेक, ब्लू इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और सतत विकास जैसे उभरते क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदर्शनी, तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ व्याख्यान, स्टार्टअप शोकेस, बी टू बी बैठकें और उद्योग–अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने वाले विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

गुरुवार को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में तीन नोबेल पुरस्कार विजेता भाग ले रहे हैं। इसके अलावा तीन हजार से ज्यादा डेलिगेट्स इसमें आयेंगे जिसमें ज्यादातर युवाओं की भागीदारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और उद्योग के बीच साझेदारी को मजबूत करना तथा भारत को वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में नए

अवसर तैयार करना है। सम्मेलन में 19 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रालयों, वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग संगठनों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी भी प्रस्तावित है।

इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत डीप ओशन मिशन के तहत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। डीप ओशन मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को नई ऊंचाई देगा और इसके माध्यम से देश ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग कई दशक तक इस क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन अब सरकार समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग और आर्थिक विकास के नए अवसरों पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

इसरो ने स्टड3 रॉकेट के CE20 क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण, बढ़ गई पेलोड क्षमता

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने स्टड3 रॉकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो ने अपने स्वदेशी सीई20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 किलोन्यूटन (kN) के बढ़े हुए थ्रस्ट के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण 9 सितंबर को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। यह 'फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट' आने वाले स्टड3 मिशन के C32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज के लिए किया गया था।

CE20 इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करता है। 220 kN का यह बढ़ा हुआ थ्रस्ट भारत के सबसे भारी ऑपरेशनल लॉन्च वाहन (स्टड3) को अंतरिक्ष में और अधिक भारी पेलोड ले जाने में सक्षम बनाएगा। इस नए C32 अपर स्टेज में पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा ईंधन आ सकता है, जिससे रॉकेट का प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाएगा।

इस परीक्षण के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन टैंक प्रेशराइजेशन मॉड्यूल (LTPM) के प्रदर्शन को भी परखा गया। इसे C32 स्टेज के लिए विकसित किया गया है, जिसका उपयोग भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान

मिशन 'गगनयान' में किया जाएगा। यह सिस्टम उड़ान के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन के सही प्रवाह के लिए आवश्यक दबाव को बनाए रखने में मदद करता है।

स्टड3 इससे पहले चंद्रयान मिशन और कई कमर्शियल उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। इस उन्नत इंजन और इससे जुड़े सिस्टम के सफल ग्राउंड टेस्ट का उद्देश्य ऑपरेशनल मिशनों से जुड़े जोखिमों को कम करना है। इससे भारी उपग्रहों के लॉन्च में मदद मिलेगी और भारत अपने पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन के और करीब पहुंच गया है।

यूआईडीएआई ने लॉन्च किया आधार फेस ऑथेंटिकेशन एसडीके, अब एक ही ऐप में होगा प्रमाणीकरण

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन एसडीके और आधार फेस ऑथेंटिकेशन सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। इस पहल से बैंक, फिनटेक कंपनियां और अन्य इकोसिस्टम पार्टनर अपने मोबाइल एप्लिकेशन में आधार के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन को सीधे एकीकृत कर सकेंगे। इससे बीएफएसआई क्षेत्र में आरबीआई द्वारा अनिवार्य बहु–कारक प्रमाणीकरण के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल आसान होने के साथ उपयोगकर्ताओं को भी अधिक सहज अनुभव मिलने की उम्मीद है।

आधार फेस ऑथेंटिकेशन एसडीके यूआईडीएआई की फेस ऑथेंटिकेशन क्षमता को सीधे एंड्रॉयड और आईओएस के मूल एप्लिकेशन में उपलब्ध कराता है। इससे उपयोगकर्ताओं को प्रमाणीकरण के लिए एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने की जरूरत नहीं होगी। यानी बैंकिंग, बीमा या ब्रोकिंग जैसे एप्लिकेशन में ही आधार फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

रेडी–टू–यूज एसडीके में एआई/एमएल आधारित लाइवनेस और एंटी–स्पूफिंग क्षमताएं शामिल हैं। इससे इकोसिस्टम पार्टनर के लिए फेस ऑथेंटिकेशन को अपने एप्लिकेशन में एकीकृत करना आसान होगा। एसडीके प्रमाणीकरण डेटा के सुरक्षित प्रबंधन और एन्क्रिप्शन का भी समर्थन करता है। इसे उपभोक्ताओं के स्मार्टफोन पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

यूआईडीएआई के इस समाधान से सरकारी विभागों, बैंकों, फिनटेक कंपनियों और अन्य संगठनों को फेस ऑथेंटिकेशन आधारित सेवाओं को अधिक कुशलता से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर बीएफएसआई क्षेत्र में ग्राहक ऑनबोर्डिंग और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

एसडीके के साथ यूआईडीएआई ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन सैंडबॉक्स भी लॉन्च किया है। यह एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण है, जहां संगठन किसी सेवा को उत्पादन में शामिल करने से पहले पूरी फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को एकीकृत, परीक्षण और सत्यापित कर सकेंगे।

सैंडबॉक्स में डेवलपर और क्वालिटी एश्योरेंस टीमें उपयोगकर्ता प्रोविजनिंग और सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और कार्रवाई संबंधी सत्यापन जैसे प्रमुख चरणों का परीक्षण कर सकेंगी।

740 टेढ़ी–मेढ़ी सीढ़ियां और 360 डिग्री का खूबसूरत व्यू, 'द रॉक ऑफ गुआटापे' को देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। कोलंबिया में स्थित 'द रॉक ऑफ गुआटापो' दुनिया के सबसे बड़ी प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं में से एक है। ये कोलंबिया के गुआटापो में शहर में स्थित है। ये खूबसूरत चट्टान लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी टेढ़ी–मेढ़ी सीढ़ियों के लिए मशहूर है। आइए जानें द रॉक ऑफ गुआटापो का इतिहास क्या है और ये क्यों इतना खास है।

इस विशाल ग्रेनाइट पत्थर का इतिहास लाखों साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि कोलंबिया की स्थानीय जनजाति तहामी इस पत्थर को पूजते थे और इसे मोहरा कहते थे। हालांकि, काफी लंबे समय तक ये वहां के लोगों के लिए सिर्फ एक चट्टान था और किसी ने इस पर न तो चढ़ने की कोशिश की और न ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी।

इसके बाद साल 1954 में लुइस एडुआर्डो विलेगास नाम के एक स्थानीय निवासी ने इस चट्टान पर चढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ चढ़ाई करने का फैसला लिया और इस चट्टान की दरारों में लकड़ी के खूंटे फंसाकर 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद शिखर पर पहुंचे।

इसके बाद लुईस विलेगास ने इस चट्टान पर अपना अधिकार बना किया और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शुरू किया। आज इस चट्टान पर पहुंचने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी और इस पर बनी

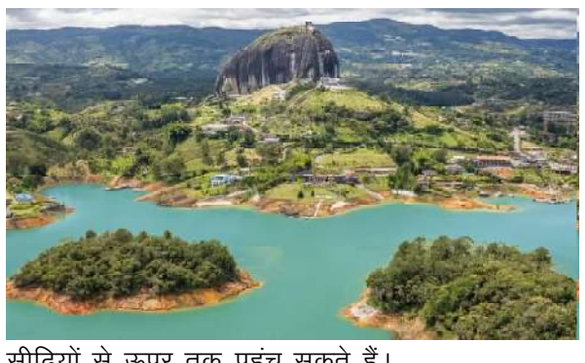

सीढ़ियों से ऊपर तक पहुंच सकते हैं।

ये एक मोनोलिथ चट्टान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 220 मीटर है और इसका वजन 10 लाख टन से भी ज्यादा माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी दरार के बीच बनाई गई जिग–जैग सीढ़ियां, जो इस चट्टान के शिखर पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता है।

इसके शिखर पर पहुंचने के लिए आपको लगभग 740 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचने पर आसपास के पूरे इलाके का 360 डिग्री व्यू दिखता है। 1970 के बाद बने हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध के कारण आसपास के इलाके में बने खूबसूरत द्वीप और झीलों का खूबसूरत नजारा भी यहां से दिखाई देता है। इस चट्टान के शिखर पर एक तीन मंजिला टावर भी है। साथ ही, ऊपर पहुंचकर आप यहां के लोकल हैंडिक्राफ्ट देख सकते हैं और स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं।

भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार–विमर्श किया।

प्रस्तावित समझौतों में पिनेकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। रूस ने नई दिल्ली में आयोजित इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम में अपने क्षेत्रीय एसजे–100, एमसी–21 और आईएल–114–300 विमानों का प्रदर्शन भी किया।

सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन पहले ही भारत में सुपरजेट–एसजे–100 यात्री विमान के लाइसेंस के अंतर्गत संयुक्त निर्माण और रखरखाव के लिए प्रारंभिक समझौता कर चुकी हैं। श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में विमान निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन की प्रगति पर चर्चा की।

श्री नायडू ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए भारत और रूस के बीच संबंधों को खरीदार–विक्रेता से आगे बढ़ाकर संयुक्त निर्माण और व्यापक औद्योगिक सहयोग में बदलने का मजबूत अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत–रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और विमानन रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है। दो दिन का 'इनोप्रोम इंडिया' कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ।

पैकेज्ड फूड पर सख्त चेतावनी लेबल के लिए तैयार एफएसएसएआई, सुप्रीम कोर्ट में जताई सहमति

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह पैकेज्ड फूड उत्पादों पर शुरुआत से ही सख्त चेतावनी लेबल लागू करने के लिए तैयार है। यह बयान फ्रंट–ऑफ–पैक लेबलिंग को दो चरणों में लागू करने के प्रस्ताव पर उठ रहे सवालों के बीच आया है।

FSSAI ने पिछले महीने पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के लिए लाल रंग के हेक्सागोन आकार के चेतावनी लेबल का प्रस्ताव रखा था। यह लेबल उन उत्पादों पर लगाए जाने थे, जिनमें तय सीमा से अधिक मात्रा में कम से कम दो श्रेणियों–एडेड शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैटकृमें से सामग्री मौजूद हो।

प्राधिकरण ने लेबलिंग नियमों को दूसरे चरण में और सख्त करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, इस दो–चरणीय व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी। उनका कहना था कि शुरुआती नियम अपेक्षाकृत नरम होने के कारण उपभोक्ताओं को स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी मिलने में देरी हो सकती है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से दो चरणों में नियम लागू करने के पीछे के तर्क पर सवाल किया। इसके बाद FSSAI ने अदालत को बताया कि वह शुरुआत से ही सख्त चेतावनी लेबल लागू करने पर विचार करने के लिए तैयार है।

इसमें ऐसे उत्पादों पर भी चेतावनी लेबल लगाने का विकल्प शामिल है, जिनमें इन तीन में से किसी एक–एडेड शुगर, नमक या सैचुरेटेड फैट–की मात्रा तय सीमा से अधिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य को।

जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर।" पीठ ने कहा कि इस मामले में सभी हितधारकों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय हित से जुड़ा विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार को बाद में जारी होने वाले आदेश का अध्ययन करने और अपनी सुझाव देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।–(इनपुटः IANS)

राष्ट्रीय वन शहीद दिवसः वनों की रक्षा के लिए प्राण गंवाने वालों को नमन करने का दिन

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। भारत में प्रतिवर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, यानी National Forest Martyrs Day मनाया जाता है. देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के बलिदान का सम्मान करने के लिए देश में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी. वनों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों द्वारा देशभर में विभिन्न तरह की गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं.

वर्ष 2013 के 11 सितंबर को पहली बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में National Forest Martyrs Day मनाने की आधिकारिक शुरुआत की थी. इस दिवस के चुनाव के पीछे इस दिन का ऐतिहासिक महत्व होना है. वास्तव में 11 सितंबर ही वह दिन था, जब राजस्थान के खेजड़ली गांव में नरसंहार हुआ था. यही वह दिन था जब बिश्नोई समुदाय के सदस्यों ने मारवाड़ साम्राज्य में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था. यह दिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व की भी याद दिलाता है.

जब एक ग्रामीण महिला अमृता देवी भिड़ गयी महाराजा अभय सिंह के सैनिकों से और फिर शुरू हुआ टकराव 11 सितंबर, 1730 का दिन उस भयावह दिवस की याद दिलाता है जब खेजड़ली के अनेक वन प्रेमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. वास्तव में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह एक नये महल का निर्माण करा रहे थे. जिसके लिए उन्हें खेजड़ी के लकड़ी की जरूरत थी. इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए महाराजा ने राजस्थान के थार जिले के खेजड़ली गांव के खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया. राजा के आदेश का विश्नोई समाज द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, परंतु उसकी मांग अनुसुनी कर राजा के आदेश का पालन हुआ और कई सारे पेड़ काट डाले गये. वास्तव में खेजड़ी के पेड़ बिश्नोईयों की जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे और उनकी पारिस्थितिक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी. पेड़ों के कटने से ग्रामीण क्षुब्ध हो उठे. अन्य पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक बिश्नोई महिला अमृता देवी और उनकी तीनों बेटियां खेजड़ी के पेड़ों से लिपट गयीं. बिना इस बात से डरे कि पास ही कुल्हाड़ी लिये पेड़ काटने पर आमादा महाराजा अभय सिंह के सैनिक खड़े थे.

अमृता देवी और उनकी बेटियां द्वारा अपनी जान की परवाह किये बिना पेड़ों से लिपटने के साहसी कार्य का यह समाचार तेजी से आसपास फैल गया. इसके बाद वहां जल्द ही ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गयी, जो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थी. इस प्रकार बिश्नोइयों और महाराजा के सैनिकों के बीच टकराव बढ़ गया. परिणामस्वरूप महाराजा के सैनिकों द्वारा भयानक नरसंहार को अंजाम दिया गया, जिसमें 363 से अधिक बिश्नोई पेड़ों की रक्षा करने के प्रयास में मारे गये.

...जब दहल उठा था दुनिया का सबसे ताकतवर देश, 9/11 आतंकी हमले की बरसी आज

वॉशिंगटन, 10 सितम्बर। 11 सितंबर 2001 का दिन शायद ही कोई भूला होगा. इसी दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर घातक आतंकी हमला हुआ था. आतंकियों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया था. इस हमले में करीब 3 हजार लोगों की जान चली गई थी. इस हमले से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी. इसे दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में गिना जाता है. आज अमेरिका पर हुए इस हमले के कई साल हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 9/11 हमले के पीड़ितों को सम्मानित करने और उन्हें याद करने के लिए देशभर में यात्रा करेंगे.

11 सितंबर 2001 की सुबह अल–कायदा के आतंकियों ने चार विमान हाईजैक कर लिया था. इनका मकसद विमान को अलग–अलग ऐतिहासिक स्थलों पर क्रैश कराने का था. सबसे पहला प्लेन क्रैश अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 का हुआ, जो न्यूयॉर्क शहर में सुबह 8.46 बजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया था. ठीक इसके 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 दक्षिणी टावर से टकराई. वहीं करीब 9.37 बजे अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराई और चौथी हाईजैक फ्लाइट 93 का लक्ष्य व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाना था लेकिन यात्रियों से लड़ाई के कारण आतंकियों के हाथ से विमान का नियंत्रण छूट गया और यह पेन्सिलवेनिया के शैंक्सविल में मैदानी इलाके में जा गिरा.

आतंकियों की ओर से किए गए इन चार हमलों में 2977

लोगों की मौत हुई थी. इनमें 19 हाईजैकर आतंकी भी शामिल हैं. वहीं जो लोग मारे गए, उनमें चार विमानों में सवार 246, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके आसपास के इलाके में 2606 और पेंटागन में मौजूद 125 लोग शामिल थे. मारे गए लोगों में ज्यादातर आम नागरिक शामिल थे. वहीं राहत और बचाव कार्य के दौरान 344 बचावकर्मी, 71 पुलिसकर्मी और 55 सैन्यकर्मी भी मारे गए थे.

11 सितंबर 2001 के हमले के एक महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था. अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली. इसके करीब दस साल बाद 2011 में अमेरिकी सैना ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के ऐबटाबाद में मार गिराया. अमेरिका ने इसी साल यानी 2022 में ही ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ और खूंखार आतंकी अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया. ये हमला काबुल में किया गया. अल जवाहिरी 9/11 हमले का मुख्य आरोपी था और उस पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था.